शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

प्रदेश में 13 जून के बाद खुलेंगे स्कूल

सीएम ने एक क्लिक से जमा किए बच्चों के खातों में 146 करोड़

भोपाल, मुप्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मध्यान्ह भोजन योजना की मई और जून महीने के 37 दिनों की 145.92 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से 66.27 लाख विद्यार्थियों के खातों में जमा की। इस मौके पर सीएम ने विद्यार्थियों से चर्चा में कहा कि प्रदेश में स्कूल 13 जून के बाद खुलेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण है, वैसे तो हमारी कोशिश है कि स्कूल खुल जाएं, स्कूल खुलना भी तय है, लेकिन अंतिम फैसला थोड़े दिनों के बाद लेंगे। कोरोना से निपटना भी है, इसलिए पूरी तरह से सभी चीजें ओपन नहीं कर सकते। सीएम ने बच्चों से उनकी पढ़ाई, कोरोना से बचाव के लिए अपनाए जा रहे उपायों और करियर के संबंध में जानकारी भी ली।

अब तक 347 करोड़ जमा हुए : इससे पूर्व मार्च और अप्रैल की 33 दिन की राशि 117.11 करोड़ रुपए जमा की जा चुकी है। इसके अलावा भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को भी कुल 84 करोड़ की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया गया है। कोरोना संकट की अवधि में कुल 347 करोड़ रुपए योजना के अंतर्गत जमा करवाए गए हैं।

प्रदेश में आने-जाने के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं

मप्र में एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने पास सिस्टम समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में आने-जाने के लिए अब ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। सीएम शनिवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रदेश में सिर्फ भोपाल, इंदौर व उज्जैन जिले से अन्य जिले में जाने के लिए ई-पास अनिवार्य था। बाकी जिलों से बाहर जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता पहले ही समाप्त कर दी गई थी।

देश अब तीन फेज में होगा अनलॉक

8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल्स होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे

सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लोगों के मूवमेंट पर अब रोक नहीं, पूरे देश में रात 9 से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू

सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, बड़े जमावड़े बंद रहेंगे

जेएनएन, नई दिल्ली

दो महीने से ज्यादा वक्त के बाद अब भारत खुलने की तरफ बढ़ चुका है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। आठ जून से धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा। लॉकडाउन को खोलने के लिए गृह मंत्रालय ने तीन फेज की एक लिस्ट तैयार की है। इसी के अनुसार लॉकडाउन को खोला जाएगा। अब जो नए नियम आए हैं, उनमें कर्फ्यू का समय भी बदल गया है। देश में नाइट कर्फ्यू ■ शेष पृष्ठ 7 पर

पहला फेज 8 जून से

धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस, शॉपिंग मॉल्स खुल सकेंगे।

दूसरा फेज जुलाई में

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खोलने पर फैसला होगा।

तीसरा फेजः इन पर फैसला बाद में

इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े।

फेज 1 में क्या खुलेगा

पहला फेज 8 जून से शुरू होगा। 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्त्रां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।

फेज 2 में क्या खुलेगा

दूसरे फेज में सरकार ने स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।

फेज 3 में क्या खुलेगा

ये आखिरी फेज होगा। इसमें भारत का नजारा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 24 मार्च के पहले होता था। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम को फेज 3 में खोला जाएगा। हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।

बड़ी राहत

राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई राज्य पब्लिक हेल्थ और उसके असर के कारणों के आधार पर लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे इस तरह के मूवमेंट से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रियाओं को अमल में लाना होगा।

बड़ी बंदिश

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगे।

कंटेनमेंट जोन

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।

बफर जोन

राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।

गाइडलाइन का सख्ती से पालन जरूरी

- राज्य और केंद्र शासित सरकारें गाइडलाइन में किसी भी स्थिति में ढील नहीं देंगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी की गई है। सभी जिला मजिस्ट्रेट गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएंगे।
- अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरोग्य सेतु ऐप

दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है। जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की सलाह देगा।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्क प्लेस की कॉमन गाइडलाइन

- यात्रा के दौरान या किसी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा।
- पब्लिक प्लेस पर दो लोगों के बीच दो गज की दूरी जरूरी होगी।
- बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही रहेगी। शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति।
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
- जितना ज्यादा संभव हो सके, वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए।
- कॉमन एरिया में सभी एंट्री और एग्जिट प्वांइट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर, हैंड वॉश उपलब्ध कराना होगा।
- ह्यूमन टच में आने वाली सभी जगहों जैसे दरवाजों के हैंडल को लगातार सैनिटाइज करते रहना होगा।
- वर्क प्लेस पर सभी इम्प्लॉइज को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

माशिमं ने परीक्षा देने वाले लाखों बच्चों को अपने हाल पर छोड़ा

अपने घरों की ओर पहुंचे बच्चों के लिए परीक्षा देना अग्निपरीक्षा से कम नहीं

प्रवेश पत्र हैं पर लॉकडाउन में बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना मुश्किल

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

माध्यमिक शिक्षा मंडल की एक गलती से प्रदेश के लाखों निर्धन बच्चे 12वीं की शेष परीक्षा देने से वंचित रह सकते हैं। कारण भी है कि मंडल ने जो नीति निर्धारित की है उसके अनुसार सभी बच्चे परीक्षा दें यह संभव नहीं लग रहा है।9 जून से माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए 12वीं के बकाया प्रश्नपत्रों की परीक्षा करवाने जा रहा है। मंडल ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अपनी मूल संस्था या परीक्षा केंद्र छोड़कर अपने घरों की ओर पहुंचा विद्यार्थी जहां होगा उसे वही परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को एक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आपदा और लॉकडाउन की इस घड़ी में यह आदेश लाखों बच्चों के लिए मुसीबत का कारण बन रहा है।

वजह भी है कि यदि विद्यार्थी भोपाल में पढ़ता था और बीमारी संकट के कारण वह अपने गांव पहुंचा है। तो वहां पर ऑनलाइन आवेदन करना मुश्किल है। साइबर कैफेऔर किओस्क की दुकान कई जिलों में बंद है। प्रदेश में हजारों निर्धन बच्चों के पास एंड्राइड मोबाइल नहीं है। ऐसे में इन बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संकट का कारण बना हुआ है। इस संदर्भ में मंडल की सक्षम अधिकारी दिनभर लगातार बात करने से बचते रहे हैं।

हेल्पलाइन में खर्राटे लेते हैं काउंसलर

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों की समस्या के समाधान हेतु हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की थी। विद्यार्थियों के आरोप के मुताबिक वह मजाक बन गई है। गुना शिवपुरी छतरपुर दतिया शहडोल रीवा सहित अन्य जिलों की कई छात्रों ने पीड़ा बताई है कि यहां फोन लगाने पर काउंसलर फोन रिसीव नहीं करते हैं। यदा.कदा फोन उठ भी जाता है तब भी इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं बताया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि हेल्पलाइन में मोटी वेतन पाने वाले मंडल की विद्युत शाखा के अधिकांश व्याख्याता काउंसलर बने। जो यहां पर दिन भर टेबल पर पैर पसार कर खर्राटे लेते हैं। मंडल में आला अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। इसमें मांग की गई है कि सिर्फप्रवेश पत्र दिखाने पर ही परीक्षा देना अनिवार्य किया जाए। लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रवेश पत्र दिखाने पर बच्चे क्यों नहीं दे सकते परीक्षा

राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा है कि मंडल परीक्षाओं में विद्यार्थियों की फजीहत करने जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करवाकर एक और जहां मंडल कहीं ना कहीं अपने चहेतों का नफा देख रहा है तो दूसरी हो छात्रों को परेशान करने का भी यही तरीका है। जब विद्यार्थी के पास प्रमाणित प्रवेश पत्र है तो आखिर ऑनलाइन आवेदन करवाने की क्या जरूरत है। विद्यार्थी प्रवेश पत्र दिखाकर भी कहीं पर परीक्षा दे सकता है। इस संदर्भ में मंडल को तत्काल संशोधित आदेश जारी करना चाहिए।

विद्यार्थियों के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर का कहना है कि विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। श्री राठौर का कहना है कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संभव नही है। प्रदेश के जितने भी मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालय हो। उनमें अधिकांश छात्र दूसरे जिले गांव और शहरों की पढ़ते हैं। लॉक डाउन होने के कारण यह बच्चे अपने घरों की ओर चले गए हैं। इनके लिए प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा कराना अनिवार्य करना चाहिए। इस संबंध में मंडल को पत्र लिखा जाएगा।

तत्काल निरस्त हो परीक्षा

मध्य प्रदेश समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दुबे का कहना है कि 12वीं की परीक्षा तत्काल निरस्त होना चाहिए। हम इस संदर्भ में पहले भी मंडल सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख चुके हैं। श्री दुबे का कहना है कि इंदौर उज्जैन भोपाल खरगोन सहित कई जिले हैं जहां परीक्षा कराना संभव नहीं है क्योंकि यहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुरेश दुबे का कहना है कि मंडल को विद्यार्थियों की परेशानियों से कोई चिंता नहीं है। मंडल की डिप्टी सेक्रेटरी शीला दाहिमा द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने का आदेश जारी किया गया। जो कहीं से भी उचित नहीं है।

समझ में नहीं आ रहा शिक्षा मंडल का आदेश

मप्र शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुभाष सक्सेना का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मूल परीक्षा केंद्र छोड़कर अपने घरों की ओर पहुंचे विद्यार्थियों के लिए जो आदेश जारी किया गया वह समझ से बाहर है। सक्सेना का कहना है कि खासकर ग्रामीण इलाकों में गरीब बच्चों के लिए परीक्षा देने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं है। ग्रामों में संचार साधनों का अभाव है तो कई शहरों में भी इस समय एमपी ऑनलाइन के किओस्क बंद है। मंडल को तत्काल इस पर विचार करना चाहिए।

ढाई वर्ष पूर्व अपनी घोषणा पर अमल करने मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से की रिपोर्ट तलब

तीसरे कार्यकाल में नसरुल्लागंज में शिक्षकों को प्रमोशन देने की थी घोषणा

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

मंत्री परिषद विस्तार के कयासों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने तीसरे कार्यकाल में की गई घोषणा पर अमल करने के लिए सक्रिय हुए हैं। मामला शिक्षकों की पदोन्नति पदनाम का है। विभाग के अधिकारी तो इस मामले में सोते रहे लेकिन जब मुखिया के संज्ञान में अभी यह बात आई तो उन्होंने सीहोर कलेक्टर सिरपुर तलब की है। सीएम ने तत्काल टीचरों को यह लाभ देने के लिए अफसरों को भी निर्देशित कर दिया है।

बता दे की वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के पूर्व सीहोर के नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षक संघ के एक कार्यक्रम में शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम देने की घोषणा की थी। या घोषणा होने के बाद शिक्षक लगातार विभाग के संज्ञान में यह बात लाते रहे लेकिन आरोप है कि यहां अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

हाल ही में सीएम की घोषणा का एक वीडियो वायरल हुआ तो इस पर गंभीरता से विचार भी हुआ। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए सरकार विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती। इसलिए प्रदेश शासन के अधिकारियों ने घोषणा को संज्ञान में लेते हुए सीहोर कलेक्टर से वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत पुराने शिक्षक तमाम उच्च योग्यताओं के बावजूद 30 से 40 वर्ष से बिना पदोन्नति के उसी पद पर कार्य कर रहे है। जबकि उनसे काफी जूनियर शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक से अध्यापक बने नवीन संवर्ग के शिक्षको की पदोन्नति कर दी गई। यही नहीं जूनियर संवर्ग की पदोन्नति के बाद उन्हें स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग में मर्ज करने से इन दोनों विभागों में विधि सम्मत विसंगति उत्पन्न हो गयी है। अन्य विभागों में ऐसी स्थिति नहीं है।

नसरुल्लागंज शिक्षक सम्मेलन की सीएम ने घोषणा की थी

बताते चलें कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 दिसंबर 2017 को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में समग्र शिक्षक संघ के एक सम्मेलन में पदोन्नति से वंचित शिक्षकों को योग्यतानुसार क्रमोन्नति का पदनाम देने की घोषणा की थी। संगठन अध्यक्ष सुरेश दुबे का कहना है कि घोषणा का परिपालन कराने के लिए विधिवत पत्र सीहोर कलेक्टर ने शासन को भेजा था लेकिन पिछले शिवराज शासनकाल में इस मुद्दे पर अफसरशाही के रोड़ा अटका या गया। इस कारण प्रदेश के लगभग 40000 शिक्षक पदनाम पदोन्नति से वंचित रह गए। जिससे प्रदेश के शिक्षक सरकार से काफी नाराज रहे हैं। दुबे का कहना है किउक्त मांग आनर्थिक है। शासन पर कोई वित भार भी नहीं आएगा और भर्ती निचले स्तर पर करना पड़ेगी। शासन के करोड़ों पर की बचत होगी। उसके बावजूद विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई है।

हमने अपने कार्यकाल में चलाई थी विधिवत फाइल: पूर्व प्रमुख सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व प्रमुख सचिव एवं वर्तमान में कार्मिक विभाग की पीएस दीसि गौर मुखर्जी का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम देने के लिए फाइल चलाई थी। शिक्षकों की मांग पर बाकायदा लोक शिक्षण संचनालय से प्रस्ताव मांगा गया था। उसके बाद उनका तबादला हो गया था। फिर क्या हुआ इस बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। पिछली महीने इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग की मौजूदा प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने कहा था कि पदोन्नति से संबंधित नियम तैयार हैं। प्रमोशन करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है। हालांकि शिक्षकों को कहना है कि अभी प्रमोशन संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं।

कंटेनमेंट क्षेत्र में सख्ती से लागू हो लॉकडाउन

भोपाल (आरएनएन)। बैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत संत नगर मे लगातार मिल रहे कोरोना मरीजो के मिलने पर आज कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, तरुण पिथौड़े द्वारा निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने एसडीएम और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्र में पाए गए कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें आइसोलेट, क्वॉरेंटाइन और स्वास्थ्य उपचार देने के लिए अस्पतालों में भर्ती कराने के बाद नियमित लोगो को समझाइश दी जाए, साथ ही क्षेत्र मे यदि किसी को सर्दी खासी, बुखार आ रहा है तो पहचान होने पर सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, जांच और उपचार किया जाए। लोगों को अन्यत्र स्थान पर भेजा जाएए जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों मे लाउडस्पीकर से एलाउंसमेंट किया जाए। सभी लोगों को समझाईश दी जाए की आप अपने घरों मे रहे। मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। अपने आप को सेनिटाइज करते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कलेक्टर ने सर्विलास टीम को निर्देश दिए कि संक्रमित व्यक्तियों की कॉनटेक्ट हिस्ट्री और ट्रेसिंग की जाए जिससे अन्य व्यक्तियों की पहचान सरलता से की जा सके और कोरोना से संबंधी लक्षण दिखने पर आइसोलेशन और संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रखा जा सकें। पुलिस को निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रों में बैरिकेडिंग कर आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए। दैनिक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए नगर निगम द्वारा प्रतिदिन इन क्षेत्रों में वस्तुओं का विक्रय सुनिश्चित किया जाएए जिससे संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों को इन प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर जाने से रोका जा सके।

कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र बैरागढ़ का निरीक्षण किया

प्रदेश में 15 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन

शिक्षण संस्थान खुलेंगे पर अंतिम निर्णय 13 जून के बाद : शिवराज

भोपाल, संवाददाता

मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता, लिहाजा सरकार ने यह तय किया है कि लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ाई जाएगी। हालांकि इसको लेकर क्या गाइडलाइन होंगी यह आने वाले एक-दो दिन में साफ होगा। लॉकडाउन को लेकर चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर लिया है। प्रदेश में भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहर कोरोना की चपेट में हैं लिहाजा सरकार लॉकडाउन पूरी तरह खत्म कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। प्रदेश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए 13 जून के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन सरकार 13 जून तक का इंतजार और करेगी अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो फिर स्कूल खोलने का फैसला टाला भी जा सकता है। राज्य में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी को छोड़कर बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में हैं और सभी जगह शर्तों के साथ बाजार खोल दिए गए हैं। इसी तरह प्रदेश में खेल गतिविधियां भी एक जून से शुरू हो रही हैं।

सागर जिला बना नया हॉट स्पॉट

राज्य में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी को छोड़कर बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में है और सभी जगह शर्तों के साथ बाजार खोल दिए गए हैं। इधर राज्य में सागर जिला नया हॉट स्पॉट बन गया है। यहां शुक्रवार को 24 नए मामले मिले हैं। इनमें 16 सदर, 4 मढ़िया विट्ठल नगर के अलावा मकरोनिया, मोतीनगर, सिविल लाइन और सूबेदार वार्ड में एक-एक संक्रमित मिले हैं। इसके साथ शहर में अब तक 165 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 92 सदर से हैं। जिले में 8 मौतें हो चुकी हैं।

8 जून के बाद खुलेंगे होटल, मॉल और धार्मिक स्थल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू नहीं होंगी

नई दिल्ली, स्व.स.से.

देश में लॉकडाउन धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। यह तीन चरणों में होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कर दी। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खोले जाएंगे। यही नहीं देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही होगा। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। नए दिशा निर्देशों के तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं और कोचिंग राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे। राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं। फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। आपात चिकित्सकीय सेवाओं और जरूरी सामान और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर कंटेनमेंट जोनों में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सघनता से घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी।

आवाजाही पर अब रोक नहीं : राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों की आवाजाही और माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवाजाही के लिए अलग से अनुमति लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई राज्य लोक स्वास्थ्य और उसके असर के कारणों के आधार पर लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे इस तरह की गतिविधियों से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रियाओं को अमल में लाना होगा।

रात्रिकालीन कर्फ्यू : रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगे।

बफर जोन: राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती हैं या आवश्यक होने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने 66.27 लाख विद्यार्थियों के खातों में डाले 145 करोड़

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मध्यान्ह भोजन योजना की मई और जून महीने के 37 दिनों की 145.92 करोड़ रुपये राशि एक क्लिक के माध्यम से 66.27 लाख विद्यार्थियों के खातों में जमा की। पूर्व में मार्च और अप्रैल माह के 33 दिन की राशि 117.11 करोड़ रुपये जमा की जा चुकी है। इसके अलावा भोजन तैयार करने वाले रसोईयों को भी कुल 84 करोड़ की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया गया है।

कोरोना संकट की अवधि में कुल 347 करोड़ रुपये योजना के अंतर्गत जमा करवाए गये हैं। अवकाश की अवधि में पहली बार योजना का लाभ विद्यार्थियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, कोरोना से बचाव के लिए अपनाए जा रहे उपायों और भविष्य के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव, संचालक मध्यान्ह भोजन योजना दिलीप कुमार और सचिव मुख्यमंत्री एम. सेलवेन्द्रम उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 1.13 लाख लक्षित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों तथा बाल श्रम परियोजना की शालाओं के बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत दोपहर में पका हुआ भोजन दिया जाता है। कोरोना संकट के कारण शालाओं में मध्यान्ह भोजन का वितरण करना संभव न था, इसलिये बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का फैसला लिया गया।

बच्चों के घरों तक पहुंच रहा है गेहूँ, चावल

प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत 66.27 लाख बच्चों को 26109.79 मे.टन गेहूँ एवं चावल स्व सहायता समूहों, रसाईयों, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से घर-घर जाकर वितरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह कार्य सम्पन्न होने के बाद द्वितीय चरण में 29479.65 मेट्रिक टन गेहूँ, चावल के वितरण की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।

कोरोना से बचाव के लिए सजग रहें बच्चे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना की राशि बच्चों के खाते में जमा करने के पश्चात 10 जिलों के बच्चों से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों से कहा कि उनके मामा का सभी भांजे-भांजियों को ढेर सारा आशीर्वाद है। स्कूल अभी बंद हैं। आप सभी के लिये राशन और खाद्य सुरक्षा भत्ते की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहें। जब भी स्कूल शुरू होंगे, आप सभी को किताबें और गणवेश प्रदान की जाएगी। संबल योजना के विद्यार्थियों के लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। फीस के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क बांधने और अन्य सावधानियों का पूरा पालन जरूर करें। यह कोरोना समाप्त हो जाएगा, आप सभी स्वस्थ रहने के लिए बचाव पर ध्यान दें। इससे डरना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करना है।

बाल आयोग ने सौंपी गाइडलाइन

स्कूल की 55 सीटर बस में केवल 25 बच्चों को बैठाएं

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

शासन की तैयारी 15 जुलाई से स्कूल खोलने की है। जबकि बाल आयोग सितंबर से स्कूल खोले जाने के पक्ष में है। इसे लेकर आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है और सुझाव दिया है कि 55 सीटर स्कूली बस में 25 बच्चों को ही बैठाया जाए। क्लास में बच्चों को 6 फीट की दूरी पर मास्क लगाकर बैठाने की व्यवस्था करें। ऐसे ही 150 बिंदुओं पर आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया कि गाइडलाइन स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दी है।

गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु

- स्कूल को भी पूरी तरह हर दिन सैनिटाइज करना आवश्यक होगा।
- हर पीरियड के बाद बच्चों के हाथ धुलवाए जाएं।
- यूनिफार्म को अनिवार्य न किया जाए, जिससे बच्चा हर दिन साफ नए कपड़ों में स्कूल पहुंच पाए।
- सर्दी-जुकाम होने पर अभिभावक बच्चे को स्कूल ना भेजें।
- पालकों के लिए निर्देश है कि वे कोविड-19 सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पालन करते हुए ही बच्चे को स्कूल भेजें।

शिक्षकों को खुश रहने के लिए सरकार ने तैयार करवाए कोर्स

भोपाल • डीबी स्टार

स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों को खुश रहने के गुर सिखाएगा। इसके लिए राज्य आनंद संस्थान ने विशेष रूप से अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट (अलोहा) ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। डीपीआई ने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। इस कोर्स की मदद से प्रदेश के शिक्षक प्राचार्य और अफसर लॉकडाउन में घर बैठे खुश रहने के तरीके सीख सकेंगे। इस दौरान उन्हें यह सिखाया जाएगा कि सुखी और संपन्न जीवन के मूल में क्या है?

लोक शिक्षण संचालनालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह कोर्स शुरू किया था। उसमें भोपाल जिले के 200 और राजगढ़ जिले के 100 शिक्षकों को ऑनलाइन शामिल किया गया। कोर्स के संबंध में प्रतिभागियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग उत्साहित है। इसलिए उच्च अधिकारी चाहते हैं कि विभाग के बाकी अफसर, प्राचार्य और शिक्षकों को भी इस कोर्स का लाभ मिल सके।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को नहीं किया कोरोना योद्धा घोषित, अर्जित अवकाश से भी

पूर्व मंत्री व समग्र संघ ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों को लिखा पत्र

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

कर्मचारी हलचल

मप्र स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण के अंतर्गत कार्यरत प्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना महामारी के विभिन्न आयामों में ड्यूटी पर लगाया गया हैं। शिक्षक पीपीई किट पहनकर कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी कर रहे है। लेकिन अन्य विभागों की भांति स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से इस बाबत निर्देश प्रसारित नहीं किए गए है कि ड्यूटी के दौरान इस महामारी से प्रभावित होने पर मृत्यु की दशा में कोरोना योद्धा का शिक्षकों लाभ मिले। जबकि मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत सभी विभागों को निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके विभाग के तरफ से कोई निर्देश नहीं दिए। जिससे शिक्षकों में भारी असंतोष है। शिक्षकों की इस समस्या को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, समग्र प्राचार्य एवं व्याख्याता संघ ने पत्र लिखकर इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश शर्मा का कहना है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश है कि निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित एवं 55 वर्ष से अधिक आयु होने पर किसी कर्मचारी को कोरोना महामारी से जुड़ी किसी भी गतिविधि में सलग्न न किया जाए। इसके बावजूद कई जिलों में बीमार और 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों को कोरोना महामारी से जुड़ी बचाव की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। मप्र शिक्षक कांग्रेस के प्रमुख महामंत्री आशुतोष पांडेय का कहना है कि कोरोना आपदा से जुड़े विभिन्न कार्यों से बीमार 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों की कोरोना महामारी की ड्यूटी से छूट प्रदान करते हुए, शेष संलग्न सभी शिक्षको को अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की भांति कोरोना योद्धा घोषित कर दिवंगत शिक्षकों को बीमा कवर और उनके परिजनों को त्वरित अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों को अर्जित अवकाश देने की भी मांग की है।

शिक्षक संघ की ई-बैठक आज

मप्र शिक्षक संघ की ई बैठक रविवार को आयोजित की गई है। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। संघ के महामंत्री क्षत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि बैठक में

मैनिट में 1 जून से फाइनल ईयर के एग्जाम ऑनलाइन

अन्य एनआईटीज़ के एग्जाम पैटर्न पर चर्चा के बाद लिया फैसला

- पहली बार क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े सवाल ताकि स्टूडेंट्स को लॉजिक लगाना पड़े
- स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, 15 जुलाई तक उन्हें प्लेसमेंट कंपनी जॉइन करनी है

EXAMS REINVENTED

सिटी रिपोर्टर . भोपाल

मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) में 1 से 15 जून तक फाइनल ईयर के एग्जाम ऑनलाइन होंगे। एग्जाम पूरी तरह से फेयर हों, इसके लिए पहली बार पेपर में किताबी ज्ञान वाला एक भी सवाल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आधारित सीधे सवाल पूछने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग पर सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को लॉजिक लगाना होगा। मैनिट की एग्जाम कंट्रोलर डॉ. ज्योति सिंघाई ने बताया- स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके एग्जाम ले लिए जाएं, ताकि वे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच अपनी प्लेसमेंट कंपनी जॉइन कर सकें। ऐसे में डायरेक्टर डॉ. नरेन्द्र रघुवंशी ने देश की अन्य एनआईटी से एग्जाम पैटर्न और फॉर्मेट पर बात की। स्टूडेंट्स का एक मॉक टेस्ट भी कराया, जिसमें 99% स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे। उनका एग्जाम एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। इस बीच एनआईटी जयपुर ने भी ऑनलाइन एग्जाम करवाया और रिजल्ट डिक्लेयर किया। उनकी लर्निंग, स्टूडेंट्स फीडबैक पर मैनिट ने एग्जाम शेड्यूल फिक्स किया है।

वायवा में बताना होगा लॉजिक

डिजाइनिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच वाले सवालों को हल करने में स्टूडेंट्स ने क्या लॉजिक लगाया, इसे क्रॉसचेक करने के लिए 15 जून के बाद फैकल्टी हर स्टूडेंट का ऑनलाइन वायवा भी लेगी। इस वायवा के बाद ही स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट तैयार होगा।

एग्जाम पैटर्न

- 2 घंटे के एग्जाम में स्टूडेंट्स को पेपर डाउनलोड कर कॉपी हाथ से लिखनी होगी फिर उसका पीडीएफ अपलोड करना होगा।
- 30 मिनट का बफर टाइम मिलेगा पीडीएफ कॉपी अपलोड करने के लिए

आरजीपीवी: 23 से ऑफलाइन एग्जाम, जहां हैं वहीं से दे सकेंगे

आरजीपीवी 23 जून से फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स का ऑफलाइन एग्जाम लेगा। स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में जिन भी शहरों में हैं, वहां आरजीपीवी से एफीलिएटेड कॉलेज का चुनाव बतौर एग्जाम सेंटर कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में परीक्षा के समय से 50 मिनट पहले पहुंचना होगा। इसमें आरजीपीवी के 36 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स एमटेक, बीटेक, बीफार्मा और एमबीए कोर्सेज के एग्जाम देंगे।

शिक्षकों की क्रमोन्नति रोकने का आरोप

शिक्षक संघ ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

रीवा। मध्यप्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई ने शनिवार को मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर व कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। रीवा जिला स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक, उच्च श्रेणी शिक्षक, सहायक शिक्षकों की लंबित प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमोन्नति पारित प्रस्ताव को आदेश दिलाने में गतिरोध करने हेतु यह ज्ञापन शासन के सभी जिम्मेदारों के अलावा सांसद एवं रीवा जिले के समस्त विधायकों को भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संघ के जिलाध्यक्ष डॉ कौशलेंद्रमणि त्रिपाठी ने शिक्षकों की जायज मांगों को तत्काल अमल में लाने की मांग रखी। डा.त्रिपाठी ने बताया कि संघ की जिला इकाई रीवा के द्वारा नवम्बर 2018 से लगातार पत्र के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी रीवा, कलेक्टर रीवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को समस्या से अवगत कराया जा चुका है।

जिले के शिक्षक, सहायक शिक्षक के 18सौ प्रकरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमोन्नति के मामले संज्ञान में लाये जा चुके हैं। इसके अलावा 968 अध्यापक संवर्ग के विभागीय, समिति की जांच उपरान्त शासन प्रतिनिधि के रूप में प्रतिहस्ताक्षर हेतु नस्ती सहित दिनांक 10 जनवरी 2020 से 4 मई 2020 तक पांच बार प्रस्तुत किए गए लेकिन जिला पंचायत कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण रीवा के लेखाधिकारी पुष्पराज सिंह द्वारा निरंतर आपत्तियां दर्ज कराकर शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष श्री त्रिपाठी के अतिरिक्त संभागीय संगठन मंत्री रमेश कुमार शर्मा, सचिव रमेश कुमार पाण्डेय, पूर्व प्रान्ताध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, दिनेश कुमार चतुर्वेदी, संगठन मंत्री राजेन्द्र सिंह सिकरवार, नगर अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत अधिकारी अर्पित वर्मा अवैधानिक लाभ अर्जन की अपेक्षा करते हैं। मांग पूरी न होने पर संघ ने वृहद आन्दोलन की चेतावनी दी है।

पूरे संभाग में शुरू होगा डिजिलेप अभियान

कमिश्नर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश

कहा-अब नहीं रूकेगी पढ़ाई छात्र करेंगे डिजिटल लर्निंग

जागरण, रीवा। कोरोना संकट के कारण रीवा संभाग के सभी स्कूलों में नियमित कक्षायें बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर देने के लिए शासन द्वारा डिजिटल लर्निंग इनहैन्समेंट प्रोग्राम डिजिलेप शुरू किया गया है। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ अशोक कुमार भार्गव ने जूम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिलेप अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं इनके ज्ञान का विस्तार समय का सदुपयोग आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता तथा तेजी से बदलती दुनिया से परचित कराने के लिए बच्चों की शिक्षा नियमित हो किसी भी स्थिति में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण वर्तमान में शिक्षण संस्थान प्रारंभ नहीं किये जा सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा डिजिलेप कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह विद्यार्थियों के लिए उनकी गुणात्मक शिक्षा के विकास का महत्वपूर्ण आयाम बन रहा है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियो को अपने-अपने जिले में डिजिलेप अभियान को युद्ध स्तर पर चलान को कहा। कहा कि कितनी भी कठिनाई और बाधायें आयें पर अब विद्यार्थियों की पढ़ाई नही रूकेगी। उन्हें डिजिटल लर्निंग से पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कमिश्नर डॉ भार्गव ने कहा कि कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को डिजिलेप अभियान से जोड़े जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा न आये। इसके लिए विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से प्रत्येक शिक्षक मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करें। बैठक में संयुक्त संचालक शिक्षा अंजनी कुमार त्रिपाठी, डीईओ आरएन पटेल, डीपीसी सुदामा पटेल तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के अन्य जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा संकुल प्राचार्य शामिल रहे।

बैठक में अभियान की समीक्षा करते हुए कमिश्नर डॉ भार्गव ने कहा कि रीवा संभाग में डिजिलेप अभियान में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है सभी जिला शिक्षा अधिकारी डीपीसी, प्राचार्य डाइट तथा संकुल शिक्षक समय-समय पर आनलाइन बैठकें आयोजित कर डिजिलेप के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करें। कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को डिजिलेप कार्यक्रम से अनिवार्य रूप से जोड़ें जिससे विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें। जिला स्तर पर समय-समय पर वेबनार आयोजित करके अभियान की समीक्षा करें। जिला स्तर पर आनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से डिजिलेप अभियान के संबंध में विद्यार्थियों तथा उनके पालकों से सार्थक संवाद आयोजित करें।

प्रतिदिन अभिभावकों से संपर्क करें शिक्षक

कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि हर शिक्षक प्रतिदिन कम से कम पांच अभिभावकों से अनिवार्य रूप से संपर्क करें। विशेषकर उन अभिभावकों से जिनके पास वाट्सएप की सुविधा है किंतु वे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। शिक्षक हर विद्यार्थी के पालक का फोन नंबर स्कूल में मौजूद डाटा बेस से प्राप्त करके विद्यार्थी का टेली फोन कॉल रजिस्टर बनायें जिससे विद्यार्थी को किये गये कॉल का विवरण दर्ज हो। सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर तथा दीवार लेखन एवं अन्य माध्यमों से डिजिलेप अभियान का प्रचार-प्रसार करायें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वसहायता समूहों के माध्यम से डिजिलेप अभियान के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करायें।

15 प्राचार्यों का वेतन रोकने के निर्देश

जागरण सतना । कैरियर प्रोन्नत योजना की जानकारी नही देने वाले 15 प्राचार्यों के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने उनके वेतन आहरण एवं भुगतान पर रोक लगा दी है संबंधित सभी प्राचार्यों द्वारा किये गए इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमो के विपरीत एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीन पाए जाए पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मई महीने के वेतन भुगतान पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।

यह है मामला

राज्य शासन के सभी विभागो के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नत योजना लागू करने के संबंध में प्रपत्र के मुताबिक संचालक लोक शिक्षण भोपाल द्वारा मांगी गई थी। कोरोना वायरस की दृष्टि से इस संबंध में पत्र की प्रति प्रपत्र के साथ 26 मई को सभी शंकुल प्राचार्यों को डीईओ वा आर एम एस ए के व्हाट्सएप्प ग्रुप में जानकारी प्रेषित कर चाही गई थी जिसमे यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि शंकुल केन्द्र के अंतर्गत जानकारी निरंक है तो भी निरंक होने की जानकारी भेजी जाए जिसके लिए 27 मई को भी जानकारी न भेजने वाले शंकुल प्राचार्यों को तिथि एवं समय स्मरण कराया गया था इसके बाद भी 30 मई को दोपहर 2 बजे तक इन पंद्रह प्राचार्यों द्वारा जानकारी नही दी गयी जिससे जानकारी भोपाल भेजने में अनावश्यक विलंब हुआ जिसपर वरिष्ठ कार्यालय ने नाराजगी भी जाहिर की है।

इन प्राचार्यों पर हुई कार्यवाही

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी न देने वाले जिन पंद्रह प्रचार्यों के वेतन आहरण एवं भुगतान पर रोक लगाई गई है उसमें जंनपद पंचायत मझगवां के अंदर आने वाले पाथर कछार विद्यालय के प्राचार्य रामचरण प्रजापति खोही प्रभारी प्रचार्य राजेन्द्र बहदुर सिंह नकेला प्रभारी प्रचार्य आशीष कुमार श्रीवास्तव सुखवाह के प्राचार्य पुरुषोत्तम दास सोनी गौहनी के प्रभारी प्राचार्य वीरेंद्र कुमार रामपुर बाघेलान के कृष्णगढ़ में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य नित्यानंद सिंहए रामनगर के बड़ा इटमा प्रभारी प्रचार्य राजू प्रसाद साकेतए सगौनी के प्रभारी प्रचार्य संतलाल सूर्यवंशीए अमरपाटन के करही विद्यालय में पदस्थ प्रचार्य रामसखा वर्माए ताला के प्रभारी प्राचार्य रंजुदावन शर्माए उचेहरा के ईचौल प्रभारी प्रचार्य रुचि अग्रवालए उचेहरा विद्यालय में पदस्थ प्रभारी प्रचार्य तेजभान सिंहए नागौद क्षेत्र के शिवराज पुर के प्रभारी प्रचार्य कमलेश कुमार वर्माए दुरेहा के प्रभारी प्रचार्य मार्तण्ड सिंह एवं सोहावल क्षेत्र के रेगांव विद्यालय में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव के विरुद्ध वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है।

ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर निजी स्कूलों में किताबों का धंधा

मोबाइल में मैसेज भेज कर किताब खरीदने का बना रहे दबाव निजी स्कूल संचालकों ने फिक्स करके रखी है दुकानें

जागरण, सीधी। कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवारों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने इस साल निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। लाकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। लेकिन आनलाइन पढ़ाई के नाम पर निजी स्कूलों में किताबों का धंधा शुरू हो गया है। निजी स्कूल संचालक अभिभावक के मोबाइल में मैसेज भेज उन पर किताब खरीदने का दबाव बना रहे हैं। किताब खरीदना तो ठीक अभिभावक की समस्या यह है कि हर निजी स्कूल संचालक ने अपनी स्टेशनरी दुकान फिक्स कर रही है। उस विद्यालय की किताबे सिर्फ एक पुस्तक दुकान पर ही मिलती है। फिक्स दुकान से अभिभावक महंगी किताब खरीद कर लुटने को मजबूर है।

हर साल बदल देते हैं बुक

सीबीएसई कोर्स संचालित करने वाले निजी विद्यालय बड़े पुस्तक विक्रेताओं से मिलकर अविभावों को जमकर लूटते हैं। इतना ही नहीं दूसरे साल इन किताबों का उपयोग न हो पाए।

इसलिए चालबाजी करते हुए स्कूल संचालक हर साल सेट की दो तीन किताबे बदल देते हैं। वहीं विक्रेता अविभावकों को पूरा सेट बेचते हैं। अलग से किताब न मिलने के कारण घर में पूरानी किताव उपलब्ध होने के बाद भी अविभावक 4 से 5 हजार रूपए का किताबों का सेट खरीदने को मजबूर हैं।

विद्यार्थियों को मिली खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि, पहली बार छुट्टियों में दिया गया है योजना का लाभ

शिवराज सिंह ने 66 लाख स्कूली बच्चों के लिए एक क्लिक से जमा किए 146 करोड़

भोपाल ■ एजेंसी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मध्यान्ह भोजन योजना की मई और जून महीने के 37 दिनों की 145.92 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से 66.27 लाख विद्यार्थियों के खातों में जमा की। पूर्व में मार्च और अप्रैल माह के 33 दिन की राशि 117.11 करोड़ रुपए जमा की जा चुकी है। इसके अलावा भोजन तैयार करने वाले रसोईयों को भी कुल 84 करोड़ की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया गया है। कोरोना संकट की अवधि में कुल 347 करोड़ रुपए योजना के अंतर्गत जमा करवाए गए हैं। अक्काश की अवधि में पहली बार योजना का लाभ विद्यार्थियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, कोरोना से बचाव के लिए अपनाए जा रहे उपायों और कॅरियर के संबंध में जानकारी ली।

70 दिन की अवधि के लिए दिए गए कुल 347 करोड़

उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 1.13 लाख लक्षित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों तथा बाल श्रम परियोजना की शालाओं के बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत दोपहर में पका हुआ भोजन दिया जाता है। कोरोना संकट के कारण शालाओं में मध्यान्ह भोजन का वितरण करना संभव न था, इसलिये बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का फैसला लिया गया। इस क्रम में गत 29 मार्च को बच्चों को 33 दिन की राशि 117.11 करोड़ का भुगतान किया गया था। आज 37 दिन की राशि 145.92 करोड़ का भुगतान किया गया। इस तरह आगामी 13 जून तक के लिए छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ते और रसोईयों को किए गए भुगतान को मिलाकर कुल 347 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

शनिवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राओं से चर्चा की।

बच्चों के घरों तक पहुंच रहा है गेहूं और चावल

प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत 66.27 लाख बच्चों को 26109.79 मे.टन गेहूं एवं चावल स्व सहायता समूहों, रसाईयों, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से घर-घर जाकर वितरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह कार्य सम्पन्न होने के बाद द्वितीय चरण में 29479.65 मेट्रिक टन गेहू, चावल के वितरण की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।

पढ़ाई-लिखाई की सब सुविधाएं देंगे, कोरोना से बचाव के लिए सजग रहें बच्चे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना की राशि बच्चों के खाते में जमा करने के पश्चात 10 जिलों के बच्चों से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों से कहा कि उनके मामा का सभी भांजे-भांजियों को ढेर सारा आशीर्वाद है। स्कूल अभी बंद हैं। आप सभी के लिये राशन और खाद्य सुरक्षा भत्ते की व्यवस्था की गई है। कोरोना के संकट में किसी को परेशानी न हो इसलिये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को पहले तीन माह और बाद में दो माह का राशन दिया गया। बिना राशन कार्ड वालों को भी इसका फायदा दिया गया। आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहें। जब भी स्कूल शुरू होंगे, आप सभी को किताबें और यूनिफार्म प्रदान की जाएगी। संबल योजना के विद्यार्थियों के लिएभी सरकार व्यवस्था करेगी। फीस के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क बांधने और अन्य सावधानियों का पूरा पालन जरूर करें। यह कोरोना समाप्त हो जाएगा, आप सभी स्वस्थ रहने के लिए बचाव पर ध्यान दें। इससे डरना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करना है। सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बच्चे बेहतर भविष्य बनाएं, माता-पिता का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज बच्चों को बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी किस तरह राष्ट्र के हित में निरंतर महत्वपूर्ण फैसले लेते रहे हैं। आज उनके प्रधानमंत्री पद के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा हुआ।

मामा से खूब बतियाए बच्चे भविष्य के सपने भी बताए

देवास जिले की कु. उत्तराशी ने कहा कि वो मेहनत से पढ़ने का इरादा रखती हैं। अब स्कूल खुलना चाहिए। डिंडौरी के सौरभ ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में उसने पढ़ाई भी की और खेती-किसानी के काम में भी समय दिया। सौरभ इंजीनियर बनना चाहता है। गुना के अनुज ने बताया कि उसने आठवीं के साथ नवमी की किताबें भी पढ़ ली। वह इंजीनियर बनना चाहता है। सीधी की कु. दुर्गा ने अपने पढ़ाई-लिखाई की जानकारी दी। छतरपुर के दिव्यांश और ग्वालियर की रिचा ने भी दो महीने की अध्ययन गतिविधियों की जानकारी दी। खंडवा की राधिका ने बताया कि उसने पढ़ाई के साथ मां का भी घर के काम में हाथ बंटाया। वह पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती है। सागर की गीतांजलि ने बताया कि वह भी घर के कार्य में सभी को सहयोग करती है। उसकी इच्छा आगे चलकर डॉक्टर बनने की है। विदिशा की कु. खुशी आईपीएस अफसर बनना चाहती है। उसे कोरोना संकट में पुलिस की सेवाएं देखकर भी प्रेरणा मिली है। सीहोर की कु. काजल भी पढ़ाई के प्रति गंभीर है और उसका सपना पुलिस इंस्पेक्टर बनने का है।

10 वीं-12वीं के बचे पेपर्स

आईसीएसई: छात्र जहां वहीं दे सकेंगे परीक्षा

एजेंसी | नई दिल्ली

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने 10वीं और 12वीं के बचे पेपर्स की परीक्षा देने वाले आईएससी और आईसीएसई के स्टूडेंट्स को दो बड़ी राहतें दी हैं। बोर्ड ने कई स्कूलों और अभिभावकों के आवेदन का जिक्र करते हुए बच्चों की परीक्षा का सेंटर बदलने का विकल्प देने का निर्णय लिया है। कई स्कूलों और अभिभावकों ने इसका अनुरोध किया था। लॉकडाउन के कारण कई बच्चे उस शहर में नहीं हैं, जहां उन्होंने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड ने कहा है कि छात्र जिस शहर में हैं, वहां के आईसीएसई स्कूल में परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए 7 जून तक आवेदन भेजना होगा। सेंटर बदलने के लिए अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। सीआईएससीई ने नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर कोरोनावायरस के कारण कोई छात्र 1 जुलाई से शुरू हो रही परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे कंपार्टमेंटल एग्जाम के समय दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।

कोरोना इफेक्ट | बोर्ड परीक्षा के लिए चार केन्द्र बदले, नौ जून से पेपर

दो केन्द्राध्यक्ष हुए सेवानिवृत्त, नए नियुक्त

नगर संवाददाता | रीवा

हायर सेकण्डी की शेष परीक्षा के लिए जिले के चार केन्द्र बदल दिए गए हैं। इन चार केन्द्रों को कोरोना के चलते बदला गया है। जिसमें तीन ऐसे केन्द्र हैं, जो कोरोना मरीजों के मिलने की वजह से कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं। वहीं एक केन्द्र को कोरोना संदिग्धों का ठिकाना होने की वजह से बदला गया है। वहीं इस परीक्षा में दो केन्द्राध्यक्ष भी नए होंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिन चार केन्द्रों को परिवर्तित किया गया है, उसमें शाउमावि गोड़हर, शासकीय ज्ञानोदय आवासीय अनुसूचित जाति विद्यालय, शाउमावि कटरा एवं शाउमावि खजुहा शामिल है।

24 हजार 273 परीक्षार्थी

माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने हायर सेकण्डरी की शेष परीक्षा के लिए 9 जून से 16 जून तक का समय निर्धारित किया है। इस दौरान दो पॉलियों में परीक्षा कराई जाएगी। जिले में हायर सेकण्डरी के लिए 99 केन्द्र है। यहां परीक्षार्थियों की संख्या 24 हजार 273 है।

ये दो नए केन्द्राध्यक्ष

श्रवण कुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्र की केन्द्राध्यक्ष इंदू त्रिवेदी प्राचार्य शाउमावि अगडाल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गई है, इस कारण शाउमावि मार्तण्ड क्रमांक-दो के व्याख्याता कमलेश कुमार शर्मा को यहां का केन्द्राध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सरस्वती उमावि गुढ़ परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष शाउमावि तिलया के प्राचार्य भाई लाल कोल 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इस कारण इस केन्द्र का केन्द्राध्यक्ष शाउमावि खौर कोठी के शिक्षक अनिल कुमार सिंह को बनाया गया है।

ये नए केन्द्र बनाए

शाउमावि गोड़हर की जगह अब उमादत्त उमावि ढेकहा में परीक्षा होगी। वहीं शासकीय ज्ञानोदय आवासीय अनुसूचित जाति विद्यालय में जिन परीक्षार्थियों का केन्द्र था, वे सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल में परीक्षा देंगे। शाउमावि कटरा की जगह शासकीय हाईस्कूल जमुई को केन्द्र बना दिया गया है। इसी तरह शाउमावि खजुहा का केन्द्र परिवर्तित कर शाउमावि लक्ष्मणपुर को बनाया गया है।

ट्यूशन फीस के नाम पर वसूली जा रही पूरी फीस

जिला शिक्षा अधिकारी से अभिभावकों ने की शिकायत

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर. अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी है कि ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूली जा रही है। स्कूलों की ओर से मैसेज कर फिक्स एमाउंट जमा करने के लिए कहा जा रहा है। पाँच अभिभावकों की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि राज्य शासन ने लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश जारी किया है। जॉय ट्यूटोरियल राइट टाउन और जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय नगर की ओर से फिक्स एमाउंट जमा करने के लिए मैसेज भेजा जा रहा है। स्कूल की ओर से यह नहीं बताया जा रहा है कि फिक्स एमाउंट में ट्यूशन फीस कितनी है। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील नेमा ने बताया कि शिकायत की जाँच कराई जा रही है, वहीं स्कूल संचालक अखिलेश मेबन का कहना है कि छात्रों से केवल ट्यूशन फीस ही ली जा रही है उसमें किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क शामिल नहीं है।

फर्जीवाड़ा: सरकारी शिक्षकों को बना दिया मनरेगा मजदूर

कुंडम विकासखंड की जैतपुरी पंचायत में सामने आया मामला, ग्रामीणों ने सीईओ से की शिकायत

भास्कर न्यूज | कुंडम

आदिवासी बाहुल्य कुंडम विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जैतपुरी में मनरेगा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रोजगार सहायक और सचिव ने मिलकर गांव के ऐसे लोगों के नाम मस्टर रोल में दर्शा दिए, जिन्होंने कभी मजदूरी की ही नहीं थी। हद तो तब हो गई जब मस्टर रोल में सरकारी शिक्षकों के नाम भी डाल दिए गए। इस मामले की शिकायत ग्रामीण कई बार जिम्मेदारों से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब एक बार फिर ग्रामीणों ने जनपद सीईओ से इस मामले की शिकायत की है।

जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने जनपद पंचायत में दी अपनी शिकायत में बताया है कि शिक्षक विष्णु प्रसाद, सोनेलाल, अयोध्या प्रसाद के नाम मेढ़ बंधान के कार्य में दर्शाए गए हैं। जबकि ये सभी पेशे से शिक्षक हैं। वर्ष 2013, 2014 और 2017 में मनरेगा अंतर्गत किए गए काम में शिक्षकों ने नाम दर्शाकर मजदूरी निकाली गई है। यही नहीं अब फिर से वर्ष 2020 में चल रहे मेढ़ बंधान के कार्य में शिक्षक आयोध्या प्रसाद का नाम दर्शाया गया है।

रोजगार सहायक पर वसूली का आरोप

जैतपुरी निवासी प्रहलाद सिंह, ओमप्रकाश, शिवनाथ मंगल सिंह, अनूप सिंह, रामकिशोर, तुलसीराम, सुकृति सिंह ने बताया कि रोजगार सहायक राजेश झारिया ने फर्जी नाम दर्शाकर मनरेगा में फर्जीवाड़ा किया। यही नहीं ग्रामीणों से पेन कार्ड बनवाने के नाम पर भी एक-एक हजार रुपए लिए हैं। ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना में भी फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है।

इनका कहना है

शिक्षकों के नाम मस्टर रोल में दर्शाकर मजदूरी निकालने संबंधी शिकायत मेरे पास आई है। टीम गठित कर इसका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जो भी दोषी मिलेगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ओमकार सिंह मसराम,
सीईओ जनपद पंचायत

यदि किसी परिवार का कोई सदस्य मजदूरी करता है तो मुखिया का नाम जॉब कार्ड में आता है। इसका यह अर्थ नहीं कि मुखिया भी श्रम कार्य कर रहा है।

राजेश झारिया,
रोजगार सहायक

दो प्रभारी प्राचार्यों को वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस

सतना। कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सतना जिले के दो तत्कालीन प्रभारी प्राचार्यों को दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने नोटिस जारी किया। नोटिस शा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य रामनरेश शर्मा(वर्तमान में शा.बालक उ.मा.वि. कोठी के जिला सतना के व्याख्याता) तथा शा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सतीश त्रिपाठी को जारी किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा व्याख्याता रामनरेश शर्मा की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी। तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सतीश त्रिपाठी ने व्याख्याता रामनरेश शर्मा की रोकी गई वेतन वृद्धि को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं कराई। प्रभारी प्राचार्य द्वारा सहकर्मी साथी को गलत लाभ देने के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाकर कूटरचना करते हुए वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की गई। कमिश्नर ने तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के इस कृत्य को घोर कदाचरण मानते हुए नोटिस जारी किया है। इसी प्रकरण में शा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य रामनरेश शर्मा को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है। श्री शर्मा स्वयं संस्था के प्रभारी प्राचार्य रहे लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रोकी गई एक वेतन वृद्धि के आदेश की प्रविष्टि आपकी सेवा पुस्तिका में नही मिली। इसे छुपाकर कूट रचना करते हुए वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों की स्वहित लाभ में अनदेखी की गई। साथ ही प्रभारी प्राचार्य रहते समय की वेतन वृद्धि आपके द्वारा स्वयं अपनी सेवा पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 103 में स्वीकृत कर प्रविष्टि की गई जबकि प्रभारी कार्यकाल की वेतन वृद्धियां एवं अन्य लाभ आपके जिला कार्यालय से स्वीकृत होने चाहिए। इन्हीं गंभीर कदाचरण कृत्यों के लिए श्री शर्मा को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया गया है।

प्रभारी उपयंत्री को दिया वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने सतना जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड मझगंवा के प्रभारी उपयंत्री एवं सहायक यंत्री पीसी खरे को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 10 दिवस के भीतर नहीं देने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। जारी नोटिस के अनुसार 18 मई को रीवा संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के लिए संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कार्यपालन यंत्री सतना द्वारा अवगत कराया गया कि श्री खरे अपने निर्धारित मुख्यालय में नहीं रहते हैं तथा फोन भी यदाकदा ही रिसीव करते हैं। इससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाता है। बैठक दिवस से पूर्व सतना जिले के ग्राम किटहा की नलजल योजना एक सप्ताह से मोटर पंप खराब होने के कारण बंद थी जबकि योजना नवीन सृजित हुई है। कमिश्नर ने प्रभारी उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के इन कृत्यों को गंभीर कदाचरण मानते हुए तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर उन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है।

फोटोयुक्त मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया कल से

भोपाल, (एजेंसी)। मप्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की स्थगित प्रक्रिया को एक जून से फिर शुरू किया जाएगा। इसके लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।

निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी

मतदाता सूची एक जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जाएगी। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आगामी चार अगस्त को किया जाएगा। शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही एक जून तक करना है। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड, ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन एक जुलाई 2020 को होगा। प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजैनतिक दलों को उपलब्ध कराना और स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक एक और दो जुलाई को कराना है। प्रारूप मतदाता सूची पर एक से नौ जुलाई तक दावे-आपत्ति ली जाएंगी। दावे-आपत्तियों का निराकरण 15 जुलाई तक किया जायेगा। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नगरपालिका वार्डों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य विहित स्थानों पर चार अगस्त 2020 को किया जायेगा।राज्य शासन द्वारा इंदौर एवं उज्जैन सम्पूर्ण जिलों को तथा भोपाल सहित कुछ नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र को रेड जोन में रखा गया है। अतः इन क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी। साथ ही कलेक्टर द्वारा घोषित कन्टेन्मेंट क्षेत्र में भी कार्यवाही तब-तक स्थगित रखी जाये जब-तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र से बाहर घोषित नहीं कर दिया जाता है।

इस संबंध में बिन्दुवार जानकारी आयोग को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी और जिले से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए पृथक से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरी प्रक्रिया में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जारी गाइड-लाइन का पूरा पालन किया जाय। दावा-आपात्ति केन्दों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और मास्क का उपयोग सुनिश्चित करें। प्रत्येक केन्द्र पर सेनेटाइजर उपलब्ध करवाया जाए।

डिजिलेप अभियान को पूरे संभाग में युद्ध स्तर पर चलायें:कमिश्नर

अब डिजिटल लर्निंग से होगी विद्यार्थियों की पढ़ाई

रीवा(नव स्वदेश)। कोरोना संकट के कारण रीवा संभाग के सभी स्कूलों में नियमित कक्षायें बंद हैं ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर देने के लिए शासन द्वारा डिजिटल लर्निंग इनहैन्समेंट प्रोग्राम डिजिलेप शुरू किया गया है। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने जूम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिलेप अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं इनके ज्ञान का विस्तार समय का सदुपयोग आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता तथा तेजी से बदलती दुनिया से परिचित कराने के लिए बच्चों की शिक्षा नियमित हो किसी भी स्थिति में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण वर्तमान में शिक्षण संस्थान प्रारंभ नहीं किये जा सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा डिजिलेप कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह विद्यार्थियों के लिए उनकी गुणात्मक शिक्षा के विकास का महत्वपूर्ण आयाम बन रहा है सभी जिला शिक्षा अधिकारी पूरे संभाग में डिजिलेप अभियान को युद्ध स्तर पर चलायें कितनी भी कठिनाई और बाधायें आयें पर अब विद्यार्थियों की पढ़ाई नही रूकेगी। उन्हें डिजिटल लर्निंग से पढ़ाई का अवसर मिलेगा। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को डिजिलेप अभियान से जोड़े जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा न आये। इसके लिए विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से प्रत्येक शिक्षक मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करें। हर शिक्षक प्रतिदिन कम से कम पांच अभिभावकों से अनिवार्य रूप से संपर्क करे विशेषकर उन अभिभावकों से जिनके पास वाट्सएप की सुविधा है किंतु वे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। शिक्षक हर विद्यार्थी के पालक का फोन नंबर स्कूल में मौजूद डाटा बेस से प्राप्त करके विद्यार्थी का टेली फोन कॉल रजिस्टर बनाये जिससे विद्यार्थी को किये गये कॉल का विवरण दर्ज हो। सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर तथा दीवार लेखन एवं अन्य माध्यमों से डिजिलेप अभियान का प्रचार-प्रसार करायें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वसहायता समूहों के माध्यम से डिजिलेप अभियान के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करायें।

डिजिलेप अभियान में सुधार की आवश्यकता

बैठक में अभियान की समीक्षा करते हुए कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि रीवा संभाग में डिजिलेप अभियान में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है सभी जिला शिक्षा अधिकारी डीपीसी सिंह, प्राचार्य डाइट तथा संकुल शिक्षक समय-समय पर आनलाइन बैठकें आयोजित कर डिजिलेप के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करें। कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को डिजिलेप कार्यक्रम से अनिवार्य रूप से जोड़े जिससे विद्यार्थियो के भविष्य निर्माण में शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। जिला स्तर पर समय-समय पर वेबनार आयोजित करके अभियान की समीक्षा करें। जिला स्तर पर आनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से डिजिलेप अभियान के संबंध में विद्यार्थियों तथा उनके पालकों से सार्थक संवाद आयोजित करें। डिजिलेप कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को समारोह पूर्वक डिजिवैम्प प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

प्रतिदिन शिक्षक पांच विद्यार्थियों से करें सम्पर्क

बैठक में कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि डिजिलेप, वाट्सएप समूह में भेजी जा रही शिक्षण सामग्री को शिक्षक प्रतिदिन स्वंय देखें सही समय पर विद्यार्थी तक सामग्री पहुंचना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन शिक्षक कम से कम पांच विद्यार्थियों से संपर्क करके उन्हें डिजिलेप अभियान से जोड़कर शिक्षक भागीदारी फार्म में दर्ज करें। विद्यार्थियों को समय-समय पर होमवर्क देकर उन्हें आनलाइन पढ़ाई से जोड़े रखें। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में रूके नहीं बच्चों के मन में किसी प्रकार भय न हो इसके लिए उन्हें शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही आनलाइन रचनात्मक सामग्री से जोड़ने का प्रयास करें। डिजिलेप कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों तथा अभिभावकों से सतत संपर्क रखकर उनसे अभियान के संबंध में नियमित रूप फीडबैक प्राप्त करें। डिजिलेप कार्यक्रम ई-लर्निंग का शानदार उदाहरण है। बैठक में संयुक्त संचालक शिक्षा अंजनी कुमार त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल, डीपीसी सुदामा पटेल तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के अन्य जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा संकुल प्रावार्य शामिल रहे।

डीईओ ने की ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा

-निज प्रतिनिधि-

गुना। शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेण्ड्री स्कूल बीनागंज में एक बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इस बैठक में संकुल प्राचार्य विशेष रुप से मौजूद रहे। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी रामजीलाल उपाध्याय ने बताया कि कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। उन्होने इस कक्षा में भी बच्चों की उपस्थिति शत प्रतिशत करवाने की बात कही। इस दौरान कुछ बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल नहीं होने की जानकारी सामने आई। जिस पर डीईओ ने कहा कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उनको दूरदर्शन पर आने वाले पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों में शामिल कराया जाए। । जिससे वह पढ़ाई में अन्य बच्चों से पिछड़ नहीं जाएं। उन्होने पढ़ाई के दौरान लापरवाही नहीं करने की बात कही।

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश शासन

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस
31 मई, 2020

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

क्या आप जानते हैं?

धूम्रपान करने वालों को कोरोना से संक्रमित होने की अधिक संभावना है। सिगरेट, बीड़ी अथवा हुक्का का सेवन करने से कोरोना वायरस आपके हाथ से मुंह तक एवं फिर शरीर में प्रवेश कर सकता है।

धूम्रपान करने वालों को फेफड़े की बीमारी हो सकती है या उनके फेफड़ों की क्षमता कम हो सकती है, जिससे गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अतः सिगरेट, बीड़ी अथवा हुक्के का सेवन न करें।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है। अतः तम्बाकू, गुटखा, पान, पान-मसाला या अन्य थूकने वाले उत्पादों का सेवन न करें और न ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकें।

तम्बाकू सेवन से शरीर में निम्न दुष्प्रभाव होते हैं...

- शरीर के प्रमुख अंग जैसे- मुंह, गला, ध्वनितंत्र, पेट, गर्भाशय, गुर्दा, फेफड़े आदि का कैंसर
- ह्रदय और रक्त संबंधी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक आदि
- क्षय रोग (टी.बी.)
- पुरुषों में नपुंसकता
- मोतियाबिंद
- गैंग्रीन
- महिलाओं में प्रजनन क्षमता में कमी आना और बांझपन जैसी समस्याएं

D-11024/20

तम्बाकू, सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों का सेवन छोड़ें, सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य अपनाएं।

तम्बाकू सेवन की आदत छोड़ने के लिये आज ही टोल फ्री नंबर **1800 112 356** पर कॉल करें या **011-22901701** पर मिस्ड कॉल दें।

तम्बाकू छोड़िए
आज ही

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2020

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा जनहित में जारी

देश की सेवा में समर्पित
भारतीय रेल
www.indianrailways.gov.in

1 जून, 2020 से
देशभर में शुरु होंगी 200 स्पेशल ट्रेनें

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी ये सेवायें

टिकटें ऑनलाइन (IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप) और ऑफलाइन (PRS काउंटर, टिकट एजेंट, CSC इत्यादि) माध्यमों से बुक की जा सकती हैं

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...

- सिर्फ कन्फर्म/RAC टिकट वाले यात्रियों को स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति होगी
- यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा
- ट्रेन किराए में किसी भी तरह का कैटरिंग शुल्क शामिल नहीं होगा
- यात्रा के दौरान चादर, कंबल एवं तकिया नहीं दिए जाएंगे
- सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना होगा
- सभी यात्री आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करें

ट्रेन नंबर (आगे / वापसी)	शहर से	शहर तक	ट्रेन का नाम	आवृत्ति	टिकट मिलने की प्रारंभिक तिथि (जाने की यात्रा)	टिकट मिलने की प्रारंभिक तिथि (वापसी यात्रा)
01019/20	मुंबई सीएसटी	भुवनेश्वर	कोणार्क एक्सप्रेस	प्रतिदिन	05-जून	03-जून
01061/62	लोकमान्य तिलक (ट.)	दरभंगा	दरभंगा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	24-जून	03-जून
01071/72	लोकमान्य तिलक (ट.)	वाराणसी	कामायनी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	24-जून	03-जून
01093/94	मुंबई सीएसटी	वाराणसी	महानगरी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	22-जून	02-जून
01139/40	मुंबई सीएसटी	गदग	मुंबई सीएसटी-गदग एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	02-जून
01301/02	मुंबई सीएसटी	केएसआर बेंगलुरु	उद्यान एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	02-जून
02479/80	बांद्रा (ट.)	जोधपुर	सूर्यनगरी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	02-जून
02701/02	मुंबई सीएसटी	हैदराबाद	हुसैन सागर एक्सप्रेस	प्रतिदिन	02-जून	01-जून
02715/16	एच. एस. नांदेड़	अमृतसर	सचखंड एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	03-जून
02933/34	मुंबई सेंट्रल	अहमदाबाद	कर्णावती एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
06345/46	मुंबई (एलटीटी)	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल	नेत्रावती एक्सप्रेस	प्रतिदिन	03-जून	01-जून
02955/56	मुंबई सेंट्रल	जयपुर	मुंबई सेंट्रल-जयपुर एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	02-जून
02141/42	लोकमान्य तिलक (ट.)	पाटलिपुत्र	लोकमान्य तिलक (ट.)-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस	प्रतिदिन	18-जून	03-जून
09041/42	बांद्रा (ट.)	गाजीपुर	बांद्रा गाजीपुर एक्सप्रेस	द्वि-साप्ताहिक	26-जून	07-जून
02149/50	पुणे	दानापुर	पुणे दानापुर एक्सप्रेस	प्रतिदिन	14-जून	03-जून
05645/46	लोकमान्य तिलक (ट.)	गुवाहाटी	लोकमान्य तिलक गुवाहाटी एक्सप्रेस	द्वि-साप्ताहिक	24 जून	17-जून
09037/38	बांद्रा (ट.)	गोरखपुर	अवध एक्सप्रेस	4 दिन	19-जून	03-जून
09039/40	बांद्रा (ट.)	मुजफ्फरपुर	अवध एक्सप्रेस	त्रि-साप्ताहिक	25-जून	04-जून
02156/55	ह. निज़ामुद्दीन	हबीबगंज	भोपाल एक्सप्रेस	प्रतिदिन	02-जून	01-जून
02230/29	नई दिल्ली	लखनऊ जंक्शन	लखनऊ मेल	प्रतिदिन	08-जून	03-जून
02392/91	नई दिल्ली	राजगीर	श्रमजीवी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	15-जून	03 जून
02394/93	नई दिल्ली	राजेंद्र नगर	संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस	प्रतिदिन	12-जून	01-जून
02418/17	नई दिल्ली	प्रयागराज	प्रयागराज एक्सप्रेस	प्रतिदिन	03-जून	02-जून
02420/19	नई दिल्ली	लखनऊ	गोमती एक्सप्रेस	प्रतिदिन	08-जून	02-जून
02452/51	नई दिल्ली	कानपुर	श्रमशक्ति एक्सप्रेस	प्रतिदिन	03-जून	01-जून
02560/59	नई दिल्ली	मंडुआडीह	शिवगंगा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	09-जून	01-जून
02618/17	ह. निज़ामुद्दीन	एर्नाकुलम	मंगला एक्सप्रेस	प्रतिदिन	04-जून	05-जून
04009/10	आनंद विहार	बापूधाम मोतिहारी	चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस	साप्ताहिक	07-जून	30-जून
02629/30	नई दिल्ली	यशवंतपुर	कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस	द्वि-साप्ताहिक	11-जून	10-जून
02724/23	नई दिल्ली	हैदराबाद	तेलंगाना एक्सप्रेस	प्रतिदिन	02-जून	01-जून
02916/15	दिल्ली	अहमदाबाद	आश्रम एक्सप्रेस	प्रतिदिन	03-जून	01-जून
02963/64	ह. निज़ामुद्दीन	उदयपुर	मेवाड़ एक्सप्रेस	प्रतिदिन	02-जून	01-जून
05484/83	दिल्ली	अलीपुरद्वार	महानंदा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	21-जून	02-जून
02182/81	ह. निज़ामुद्दीन	जबलपुर	ह. निज़ामुद्दीन-जबलपुर एक्सप्रेस	प्रतिदिन	08-जून	01-जून
02217/18	नई दिल्ली	वाराणसी	महामना एक्सप्रेस	त्रि-साप्ताहिक	02-जून	13-जून
02219/20	आनंद विहार	गाजीपुर	सुहेलदेव एक्सप्रेस	4 दिन	07-जून	18-जून
02233/34	आनंद विहार	गाजीपुर	आनन्द विहार गाजीपुर एक्सप्रेस	द्वि-साप्ताहिक	02-जून	13-जून
02055/56	नई दिल्ली	देहरादून	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	04-जून	01-जून
02057/58	नई दिल्ली	उना हिमाचल	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	03-जून
01016/15	गोरखपुर	लोकमान्य तिलक (ट.)	कुशीनगर एक्सप्रेस	प्रतिदिन	03-जून	25-जून
02533/34	लखनऊ जंक्शन	मुंबई सीएसटी	पुष्पक एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	15-जून
02541/42	गोरखपुर	लोकमान्य तिलक (ट.)	गोरखपुर लोकमान्य तिलक (ट.) एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	18-जून
02377/78	सियालदह	न्यू अलीपुरद्वार	पदातिक एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	12-जून
02703/04	हावड़ा	सिकंदराबाद	फलकनुमा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	03-जून	16-जून
02810/09	हावड़ा	मुंबई सीएसटी	हावड़ा-मुंबई मेल	प्रतिदिन	01-जून	19 जून
02307/08	हावड़ा	जोधपुर/बीकानेर	हावड़ा-जोधपुर/बीकानेर एक्सप्रेस	प्रतिदिन	14-जून	12-जून

ट्रेन नंबर (आगे / वापसी)	शहर से	शहर तक	ट्रेन का नाम	आवृत्ति	टिकट मिलने की प्रारंभिक तिथि (जाने की यात्रा)	टिकट मिलने की प्रारंभिक तिथि (वापसी यात्रा)
02381/82	हावड़ा	नई दिल्ली	पूर्वा एक्सप्रेस	त्रि-साप्ताहिक	03-जून	16-जून
02303/04	हावड़ा	नई दिल्ली	पूर्वा एक्सप्रेस	4 दिन	01-जून	24-जून
02245/46	हावड़ा	यशवंतपुर	दुरंतो एक्सप्रेस	5 दिन	02-जून	25-जून
02201/02	सियालदह	भुवनेश्वर	दुरंतो एक्सप्रेस	त्रि-साप्ताहिक	01-जून	02-जून
02213/14	शालीमार	पटना	दुरंतो एक्सप्रेस	त्रि-साप्ताहिक	01-जून	02-जून
02073/74	हावड़ा जंक्शन	भुवनेश्वर	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
02023/24	हावड़ा जंक्शन	पटना जंक्शन	जन शताब्दी एक्सप्रेस	1,2,3,4,5,6	08-जून	04-जून
02021/22	हावड़ा	बड़बिल	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
02296/95	दानापुर	केएसआर बेंगलुरु	संघमित्रा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	03-जून	25-जून
02792/91	दानापुर	सिकंदराबाद	दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस	प्रतिदिन	05-जून	14-जून
03201/02	पटना	लोकमान्यतिलक	पटना लोकमान्यतिलक (ट.) एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	18-जून
02553/54	सहरसा	नई दिल्ली	वैशाली एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	24-जून
02557/58	मुजफ्फरपुर	आनन्द विहार	सप्त क्रांति एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	16-जून
05273/74	रक्सौल	आनन्द विहार	सत्याग्रह एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	17 जून
02365/66	पटना	रांची	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
02565/66	दरभंगा	नई दिल्ली	बिहार संपर्क क्रांति	प्रतिदिन	01-जून	21-जून
02407/08	अमृतसर	न्यू जलपाईगुड़ी	कर्मभूमि एक्सप्रेस	साप्ताहिक	10 जून	30 जून
02357/58	अमृतसर	कोलकाता	अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस	द्वि-साप्ताहिक	02-जून	29 जून
02904/03	अमृतसर	मुंबई सेंट्रल	गोल्डन टेम्पल मेल	प्रतिदिन	03-जून	03-जून
02926/25	अमृतसर	बांद्रा (ट.)	पश्चिम एक्सप्रेस	प्रतिदिन	05-जून	02-जून
04673/74	अमृतसर	जयनगर	शहीद एक्सप्रेस	4 दिन	13-जून	30-जून
04649/50	अमृतसर	जयनगर	सरयू यमुना एक्सप्रेस	त्रि-साप्ताहिक	12-जून	29-जून
02833/34	अहमदाबाद	हावड़ा	अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	15 जून	01-जून
09165/66	अहमदाबाद	दरभंगा	साबरमती एक्सप्रेस	त्रि-साप्ताहिक	12-जून	08-जून
09167/68	अहमदाबाद	वाराणसी	साबरमती एक्सप्रेस	4 दिन	11-जून	04-जून
09045/46	सूरत	छपरा	ताप्ती गंगा एक्सप्रेस	4 दिन	11 जून	03-जून
02947/48	अहमदाबाद	पटना	अजीमाबाद एक्सप्रेस	द्वि-साप्ताहिक	15-जून	03-जून
09083/84	अहमदाबाद	मुजफ्फरपुर	अहमदाबाद-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (वाया सूरत)	प्रतिदिन	12-जून	03-जून
09089/90	अहमदाबाद	गोरखपुर	अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस (वाया सूरत)	प्रतिदिन	08-जून	03-जून
02917/18	अहमदाबाद	ह. निज़ामुद्दीन	गुजरात संपर्क क्रांति	त्रि-साप्ताहिक	01-जून	02-जून
02463/64	जोधपुर	दिल्ली सराय रोहिल्ला	संपर्क क्रांति	त्रि-साप्ताहिक	12-जून	11-जून
02477/78	जयपुर	जोधपुर	जयपुर जोधपुर एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
02065/66	अजमेर	दिल्ली सराय रोहिल्ला	जन शताब्दी एक्सप्रेस	1,2,3,5,6	01-जून	01-जून
02059/60	कोटा	ह. निज़ामुद्दीन	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	02-जून	01-जून
02555/56	हिसार	गोरखपुर	गोरखधाम एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	10-जून
02801/02	भुवनेश्वर	नई दिल्ली	पुरुषोत्तम एक्सप्रेस	प्रतिदिन	02-जून	21-जून
08183/84	टाटानगर	दानापुर	टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	02-जून
02805/06	विशाखापत्तनम	नई दिल्ली	एपी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	04-जून
07201/02	गुंटूर	सिकंदराबाद	गोलकुंडा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
02793/94	तिरुपति	निज़ामाबाद	रायलसीमा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	02-जून
09055/56	[illegible]	दिल्ली	[illegible] मेल	प्रतिदिन	03-जून	18-जून
02067/68	गुवाहाटी	जोरहाट टाउन	जन शताब्दी एक्सप्रेस	1,2,3,4,5,6	01-जून	01-जून
02091/92	देहरादून	काठगोदाम	जन शताब्दी एक्सप्रेस	2,3,5,6,7	02-जून	02-जून
02053/54	हरिद्वार	अमृतसर	जन शताब्दी एक्सप्रेस	1,2,3,5,6,7	01-जून	01-जून
02079/80	बेंगलुरु	हुबली	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
02089/90	यशवंतपुर	शिवमोगा टाउन	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	02-जून
02283/84	एर्नाकुलम	ह. निज़ामुद्दीन	दुरंतो एक्सप्रेस	साप्ताहिक	08-जून	08-जून
02075/76	कालीकट	त्रिवेंद्रम	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
02081/82	कन्नूर	त्रिवेंद्रम	जन शताब्दी एक्सप्रेस	1,2,4,5,6	01-जून	01-जून
02727/28	हैदराबाद	विशाखापत्तनम	गोदावरी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	09-जून	09-जून
02285/86	सिकंदराबाद	ह. निज़ामुद्दीन	दुरंतो एक्सप्रेस	द्वि-साप्ताहिक	04-जून	05-जून
02069/70	रायगढ़	गोंदिया	जन शताब्दी एक्सप्रेस	1,2,3,4,5,6	01-जून	01-जून
02061/62	हबीबगंज	जबलपुर	जन शताब्दी एक्सप्रेस	प्रतिदिन	01-जून	01-जून
02779/80	वास्को डी गामा	ह. निज़ामुद्दीन	गोवा एक्सप्रेस	प्रतिदिन	11-जून	08-जून

* समय और ठहराव नियमित ट्रेनों के समान होंगे   * स्थिति 30 मई 2020 को 13:00 बजे पर

स्कूल खोलने पर राज्यों की सहमति से जुलाई में फैसला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

नई दिल्ली . देशभर में 9 सप्ताह से लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की चर्चा के बीच शनिवार शाम केंद्र सरकार की 'अनलॉक-वन' गाइडलाइन सामने आई। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इनमें कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश से लॉकडाउन हटाने की घोषणा कर दी, लेकिन यह तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। हालांकि, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात करके स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला कर सकती हैं। हालांकि स्कूल खोलने पर जुलाई में ही फैसला होगा।

तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा। यह दिशानिर्देश एक जून से 30 जून तक के लिए जारी किए गए हैं।

सभी क्षेत्रों में शुरू होंगी गतिविधियां

कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सभी गतिविधियां शुरू होंगी, लेकिन केंद्र के बनाए एसओपी का पालन करना होगा।

पहला फेज

- 8 जून के बाद खुलेंगे यह स्थान।
- सभी प्रकार के धार्मिक स्थल और इबादतगाह।
- होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटिलिटी सेवाएं।
- शॉपिंग मॉल्स।
- इस पर केंद्र स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी करेगा।

दूसरा फेज : जुलाई

- स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों की अनुमति से जुलाई में खुल सकेंगे।
- राज्य सरकारें अभिभावकों और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ वार्ता कर फैसला लेंगी। फीडबैक मिलने के बाद शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर फैसला होगा।

तीसरा फेज : परिस्थितियों के अनुसार शुरू होंगी ये सर्विस

- अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम।
- सामाजिक, राजनैतिक, खेल मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक समारोह और बड़े आयोजन।

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर बढ़ेगा छूट का दायरा

प्रदेश में एक माह बढ़ सकता है लॉकडाउन, ऐलान आज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

भोपाल. प्रदेश धीरे-धीरे अनलॉक होने लगेगा। कंटेनमेंट और हॉटस्पाट क्षेत्र में सख्ती रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार रात 8 बजे प्रदेश की जनता को पूरी जानकारी देंगे। हालांकि सीएम ने शनिवार दोपहर बैठक के दौरान कहा कि लॉकडाउन अभी 15 दिन और जारी रहेगा। शाम को केंद्र के ऐलान के बाद मप्र में भी एक माह और लॉकडाउन बढ़ सकता है। मप्र अब तक केंद्र की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करता रहा है।

इंदौर में सख्ती, नए हॉट स्पॉट पर फोकस

इंदौर में रियायत देने की सरकार की मंशा नहीं है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, बुरहानपुर, ग्वालियर में भी सख्ती रखी जाएगी। प्रदेश में नए हॉट स्पॉट नीमच और सागर पर भी फोकस किया जाएगा। यहां अभी सख्ती जारी रखेंगे।

रेड जोन में भी राहत:

सरकार ग्रीन के साथ ही रेड जोन में भी राहत देगी। कंटेनमेंट क्षेत्र सील रखने, सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बाकी जगहों पर राहत रह सकती है।

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर बढ़ेगा छूट का दायरा

प्रदेश में एक माह बढ़ सकता है लॉकडाउन, ऐलान आज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

भोपाल. प्रदेश धीरे-धीरे अनलॉक होने लगेगा। कंटेनमेंट और हॉटस्पाट क्षेत्र में सख्ती रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार रात 8 बजे प्रदेश की जनता को पूरी जानकारी देंगे। हालांकि सीएम ने शनिवार दोपहर बैठक के दौरान कहा कि लॉकडाउन अभी 15 दिन और जारी रहेगा। शाम को केंद्र के ऐलान के बाद मप्र में भी एक माह और लॉकडाउन बढ़ सकता है। मप्र अब तक केंद्र की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करता रहा है।

इंदौर में सख्ती, नए हॉट स्पॉट पर फोकस

इंदौर में रियायत देने की सरकार की मंशा नहीं है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, बुरहानपुर, ग्वालियर में भी सख्ती रखी जाएगी। प्रदेश में नए हॉट स्पॉट नीमच और सागर पर भी फोकस किया जाएगा। यहां अभी सख्ती जारी रखेंगे।

रेड जोन में भी राहत:

सरकार ग्रीन के साथ ही रेड जोन में भी राहत देगी। कंटेनमेंट क्षेत्र सील रखने, सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बाकी जगहों पर राहत रह सकती है।

अब छात्रों को राहत

नई दिल्ली. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने कोरोना संकट के चलते 10वीं-12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए छात्रों को सहूलियत दी है। बोर्ड परीक्षा में छात्रों को उसी राज्य, शहर या जिले के परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की अनुमति देगा, जहां वे रह रहे हैं।

साथ चलेंगी ऑनलाइन और क्लासरूम टीचिंग की नई व्यवस्था

बच्चों को अलग-अलग दिन बुलाकर संस्थान स्टॉफ को डेढ़ गुना करके निकाल रहे हैं हल ।

संजीव अग्रवाल

सीएमडी सेज ग्रुप

को विड -19 के बाद केवल ऑनलाइन एजुकेशन ही विकल्प नहीं है। विद्यार्थियों को कैम्पस में तो लाना ही होगा। ऐसे में ऐसा क्या किया जाए कि वे कैम्पस में सुरक्षित रखें इस दूरगामी सोच के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्लासेस को शेड्यूल बनाकर चालू करने की तैयारी की है। हम अटेंडेस को आधी कर देंगे। एक ही क्लास में आधे विद्यार्थी एक दिन आएंगे तो आधे अगले दिन। जिस दिन क्लास में दूसरा बैच होगा तब पहले को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही होगी। इस दोहरी व्यवस्था को लागू करने के लिए हम दूसरों से अलग कदम उठाते हुए शेड्यूल में क्लास चलाने के लिए स्टाफ को डेढ़ गुना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कैम्पस और स्टाफ हो रहा सैनिटाइज

कैम्पस में सैनिटाइजेशन थ्री टियर में चालू किया है। बसों से लेकर क्लास तक रोजाना सैनिटाइज की जाती है। स्टॉफ सैनिटाइज टनल से अंदर आता है। अटेंडेंस आधी कर देंगे, 30 बच्चे एक दिन कर स्टाफ डेढ़ गुना कर रहे हैं।

अभी संस्थानों को ऑनलाइन एजुकेशन की ओर तो जाना ही होगा, लेकिन यह कैम्पस एजुकेशन का विकल्प नहीं है। जब कोई स्टूडेंट फिजिकली कैम्पस आता है तो उसका पेयर ग्रुप बनता है। मकसद होता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आए। आमने-सामने बच्चों के समूह बनते हैं, आपस में तुलना होती है, ये जरूरी भी है।

सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए खेल

कैम्पस में भी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि बहुत से स्पोर्टस भी होते हैं, कई स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं, जहां टच किए बिना या सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए खेला जा सकता है। हमारी कोशिश है, ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ढूंढी जाए। हमारा संस्थान हर साल मोजो कैम्प करता है, इसमें प्ले और नाइट कैम्प कराते थे। लेकिन इस साल हमने निर्णय लिया कि अब इसको ऑनलाइन कराएंगे। ई- मोजो कैम्प मे विद्यार्थियों को घर में रहकर पेरेटंस के सामने डांस करने से लेकर अन्य एक्टिविटी करनी होती है।

जॉब फ्यूचर

कोविड-19 के बाद एजुकेशन सिस्टम के बदलाव नए मौके लाएंगे : कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई के लिए तकनीकी रूप से अपडेट टीचर्स की जरूरत होगी, डिजिटल फॉर्म में बदली जाएंगी किताबें

डिजिटल एजुकेशन होगा गेम चेंजर

शकील खान
patrika.com

स्कूलों और कॉलेजों में कोरोना संकट से बचाव के लिए डिजीटल एजुकेशन ही एक विकल्प नजर आ रहा है। हालांकि इस विकल्प को अपनाने के दौरान न केवल कई संसाधनों की जरूरत होगी बल्कि कई एक्सपर्ट भी लाने होंगे जो पुराने स्टाफ को ट्रेंड कर सकें। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आरजी द्विवेदी ने बताया कि अब डिजीटल एजुकेशन के लिए जगह ज्यादा होगी। इस नए पैटर्न के लिए जहां संसाधन जुटाने होंगे वहीं कई ट्रेनर की भी नियुक्ति की जरूरत पड़ेगी जो वर्तमान में शिक्षकों को अपडेट कर सके। डिजीटलाइजेशन के रूप में बड़ी कंपनियां आ रही हैं जहां रोजगार सृजन की संभावना है।

देश हो या विदेश हर जगह परिवर्तन

ईरान स्थित तहरान में केवी एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल के प्राचार्य डॉ. एसएस डाकुआ के मुताबिक हर जगह शिक्षा मुहैया कराने में कुछ बदलाव तो होगा लेकिन क्लास रूम जरूरी है। बच्चों को स्कूल में मास्क, सेनेटाइजर सहित दूसरे कई इंतजाम करना जरूरी है। अपना देश हो या किसी दूसरी जगह हर जगह बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसे देखते हुए बदलाव की गुंजाइश तो रहेगी।

विस्तार में ही मिलेगा रोजगार

शिक्षाविद् एसएन राय ने बताया कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखते हुए शिक्षण संस्थानों को मदद की जरूरत है। शिक्षा का स्वरूप बदलने में भी उन्हें पैसा खर्च करना होगा। इसके बाद ही नए लोगों को रोजगार और विस्तार होगा। बच्चों की सुरक्षा सहित नई तकनीक वर्तमान में जरूरी है। यह सच है कि आने वाले समय में एक बार फिर रोजगार के बेहतर विकल्प मौजूद होंगे।

प्रदेश के हाल...

संसाधनों की कमी का नुकसान

अध्यापक संगठन के उपेन्द्र कौशल बताते हैं रोजगार कम हो रहे हैं। कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए व्यवस्था की बात तो कही जा रही है लेकिन प्रदेश में कई स्कूलों में संसाधन ही नहीं हैं। ऐसे में हर जगह ये संभव नहीं। अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो प्रदेश में करीब 35 हजार अतिथि शिक्षक हैं वे वापस काम पर नहीं लौट पाएंगे। ये बेरोजगार हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर भर्तियों के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी वह भी अटक गई है। आधारभूत ढांचा इतना कमजोर है।

परेशानी : स्कूल की मनमानी, चुनिंदा दुकानों से कोर्स, परेशानी में अभिभावक

स्कूल ने ऑनलाइन क्लास शुरू कराई, किताबें कंटेनमेंट जोन में

XPOSE पड़ताल

स्कूलों ने जो दुकान तय कर रखी है वह दो माह से बंद

XPOSE रिपोर्टर
xpose.bhopal@epatrika.com

भोपाल. कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच शहर के कई हिस्से कंटेनमेंट जोन घोषित हैं। इन इलाकों में कई निजी स्कूल भी हैं। इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन तो शुरू करा दी लेकिन कई बच्चों के पास अब तक कोर्स नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण चुनिंदा दुकानों पर ही स्कूल का कोर्स मिलना है। ये दुकानें कंटेनमेंट जोन में होने से खुल नहीं रही। दूसरी किसी जगह स्कूल का कोर्स उपलब्ध नहीं है।

प्रशासन ने भारत टॉकीज ओवर ब्रिज, अस्सी फीट रोड, बजरिया, जहांगीराबाद सहित कई इलाको पर स्थाई बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरह लॉक तो कर दिया है,लेकिन अंदर रहने वाले अन्य लोगों की मूलभूत जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया है। कई जगह स्थाई बैरीकेड्स लगा क्षेत्र बंद तो कर दिया लेकिन यहां न तो सामान पहुंच रहा है और न ही लोग बाहर आ पा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा और नौकरी पेशा लोगों पर हुआ। लोगों ने बताया कि कई रास्तों पर बैरीकेड्स हैं। बाहर जाने की अनुमति नहीं जबकि दफ्तर खुल चुके हैं। किसी रास्ते के बंद होने की लिखित जानकारी भी नहीं दी जा रही है। ताकि विभाग को अवगत करा सके। खासतौर पर महिला कर्मियों को खासी समस्या खड़ी हो चुकी है। हाल में इस तरह के कुछ मामले सामने जहां लोगों को रोका गया।

कंटेनमेंट के बाहर की स्थिति। अंदर स्कूल और किताबों की कई दुकानें हैं।

रास्ता बंद है.. कहीं नहीं लगी सूचना

80 फीट रोड से लगे चांदबड़ की निवासी उमा कीर, सिंधी कॉलोनी, बैरसिया रोड स्थित विजया बैंक में कर्मचारी है। बैंक खुला हुआ है,लेकिन जहां वे रहती है, वहां चारों और स्थाई बैरीकेड्स लगे हैं। कई दिनों से वे काम पर नहीं जा पाए। रास्ता बंद है लिखित में कहीं नहीं है।

किसी दुकान विशेष से किताबें खरीदने के लिए कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोर्स मटेरियल किसी एक जगह ही है तो उस पर भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

नितिन सक्सेना, डीईओ

बिना किताबों के पढ़ाई कर रहे बच्चे

जिंसी के पास कुछ निजी स्कूल हैं। सत्र शुरू हो चुका है लेकिन स्कूल कर सिलेबस जिस दुकान से मिलना है वह दो माह से बंद है। ये कहां मिलेगी इसकी कोई जानकारी भी नहीं। ऐसे में बच्चे और अभिभावक परेशान हैं। बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन तो चल रही है लेकिन पाठ्यसामग्री उनके पास नहीं है। स्कूल की ओर से कोई सूचना नहीं है।

शिक्षा विभाग में कार्रवाई

डीइओ ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर 15 संकुल प्राचार्यों का रोका वेतन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सतना. जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने राज्य शासन को भेजी जाने वाली जानकारी 30 मई तक उपलब्ध न कराने वाले 15 संकुल प्राचार्यों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी। संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए बकायदा आदेश जारी किया गया है। डीइओ द्वारा जारी आदेशानुसार, सोहावल विकासखंड की शाउमावि प्राचार्य रैगांव, नागौद की शाउमावि दुरेहा, शिवराजपुर, उचेहरा जनपद की शाउमावि बालक उचेहरा, शाउमावि इचौल, अमरपाटन जनपद की शाउमावि ताला व करही, रामनगर की शाउमावि सगौनी व बड़ा इटमा, रामपुर बघेलान की शाउमावि कृष्णगढ़ व विकासखण्ड मझगवां की शाउमावि पाथरकछार, खोही, नकैला, शुकवाह व गौहानी के संकुल प्राचार्यों का मई माह का वेतन आगामी आदेश तक आहरण व भुगतान पर रोक लगाई गई है।

दो प्रभारी प्राचार्यों को नोटिस

रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने जिले के दो तत्कालीन प्रभारी प्राचार्यों को दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है। नोटिस शा.उ.मा.वि. मुकुंदपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य रामनरेश शर्मा तथा शा.उ.मा.वि. मुकुंदपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सतीश त्रिपाठी को जारी किया गया है। नोटिस का जवाब 10 दिनों के भीतर नहीं देने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जारी नोटिस के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना द्वारा व्याख्याता रामनरेश शर्मा की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी। तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सतीश त्रिपाठी ने व्याख्याता रामनरेश शर्मा की रोकी गई वेतनवृद्धि को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं कराई। प्रभारी प्राचार्य द्वारा सहकर्मी साथी को गलत लाभ देने के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाकर कूटरचना करते हुए वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की गई। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के इस कृत्य को घोर कदाचरण मानते हुए उन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है।

बदलाव

जल्द ही 11 अंकों के हो जाएंगे मोबाइल नंबर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

नई दिल्ली. जल्द देश के मोबाइल नंबर 10 के बजाय 11 अंकों के हो सकते हैं। टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने शुक्रवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें देश में 11 अंकों के मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। ट्राई के मुताबिक यदि देश में मोबाइल नंबर के पहला अंक अगर 9 रखा जाए तो 10 से 11 अंकों के मोबाइल नंबर पर स्विच होने से देश में कुल 1000 करोड़ नंबरों की क्षमता हो जाएगी। यह 70 प्रतिशत उपयोगिता और मौजूदा नीति साथ 700 करोड़ कनेक्शन होने तक के लिए काफी है। ट्राई ने डॉन्गल्स के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबर को 10 अंकों से बढ़ाकर 11 अंक करने की भी बात कही है।